समावेशी विकास और दूरगामी परिणाम का राजनय

अचल मल्होत्रा

भारत समावेशी विकास के लिए परस्पर प्रयासरत है। इस प्रयास को मजबूती देने के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों एवं शेष विश्व से लगातार संबंध बेहतर करने के प्रयास कर रहा है। भारत की कूटनीति का ही प्रयास है कि उसे बहुपक्षीय सहयोग मिल रहा है। कुल मिलाकर राजनय इस रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है कि समावेशी विकास के भारत के एजेंडे के साथ अन्य देश भी तालमेल कर सकें

मई 2014 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद नई सरकार ने लंबी अवधि के नजरिए के साथ अभिनव पहल की एक श्रृंखला की घोषणा की। सरकार के अनेक कार्यक्रम जैसे *मेक इन इंडिया, स्किल भारत, स्मार्ट सिटी, बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल भारत, स्वच्छ भारत* आदि प्रथम दृष्टया घरेलू एजेंडे का हिस्सा नजर आए लेकिन इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए बाहरी आदानों जैसे विदेशी भागीदार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता थी। भारत की कूटनीति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बहुत कम समय में सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया। अब भारत की विदेश नीति क्रियाशील एवं व्यावहारिक है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कूटनीति का समिश्रण है। यह विकास केंद्रित है। इसके केंद्र में ऐसे बाहरी वातावरण का सृजन करना है जोकि देश के समावेशी आंतरिक विकास के अनुकूल हो। यहां मंतव्य घरेलू एजेंडे की प्राथमिकताओं के साथ कूटनीतिक पहल को भी संश्लिष्ट करना है। इसके अतिरिक्त इन प्रयासों का लक्ष्य यह है कि विभिन्न देशों के बीच बढ़ते अविश्वास को दूर किया जाए, खासकर पड़ोसी देशों के साथ और विश्व भर में परस्पर सहयोग कायम करने हेतु मित्रता और समझदारी विकसित की जाए, साथ ही एक प्रभावशाली देश के रूप में विश्व स्तर पर भारत की मौजूदगी और दृश्यता बढ़ाई जाए।

भारत के दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की सहमति हासिल करने के लिए हमारी राजनीतिक-आर्थिक कूटनीतिक पहल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यहां हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, वे केवल सकारात्मक परिणामों का संकेत हैं:

देश में समावेशी विकास हेतु कूटनीति

बुनियादी ढांचा और वित्त

गत वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत बुनियादी ढांचा निवेश कोष की घोषणा की गई थी। इस कोष ने भारत में बुनियादी ढांचे के त्वरित विस्तार हेतु भारत की योजनाओं में निवेश को समर्थन देने के लिए 75 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन और भारत ने देश के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश कोष के तहत एक साझेदारी कोष का गठन किया है। ऐसी संभावना है कि भारतीय रेल और विशेष रूप से सड़कों को विदेशी सहयोग और सहायता का लाभ मिलेगा। जापान पूर्वोत्तर में सड़कों की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराने को तैयार है। भारत और जापान के बीच उच्च गति की बुलेट ट्रेन के निर्माण पर सहमति बनी है। बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा केवल दो घंटे में तय की जा सकेगी, जिसमें अभी सात घंटे लगते हैं। जापान चेन्नई और अहमदाबाद मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 बिलियन येन का ओडीए ऋण भी देगा। वहीं फ्रांस दूसरे चरण की बंगलुरु और

लेखक अर्मेनिया और जॉर्जिया में भारत की राजदूत पद पर कार्यरत थे। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन विएना में भारत के स्थायी सहायक प्रतिनिधि रहे। नयी दिल्ली में पड़ोसी देशों के साथ संबंध विभाग के प्रभारी निदेशक हैं। आजकल विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर फ्रीलांसर के तौर पर विश्लेषण करते हैं। साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों में भारत की विदेश नीति पर व्याख्यान भी करते हैं। ईमेल: achal_malhotra@hotmail.com

कोच्चि मेट्रो परियोजनाओं और नागपुर में मेट्रो परियोजना को वित्त पोषित करेगा। बंगलुरु और नागपुर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए जर्मनी भी प्रति परियोजना 500 मिलियन यूरो का ऋण भारत को प्रदान करेगा। भारत और चीन ने रेलवे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। प्रस्तावित परियोजनाओं में मौजूदा चेन्नई-बंगलुरु-मैसूर क्षेत्र पर गति को बढ़ाना शामिल हैं। फ्रेंच कंपनी आल्सटॉम बिहार के मधेपुरा में 3.2 बिलियन यूरो के निवेश के साथ इलैक्ट्रिक इंजन संयंत्र का निर्माण करेगी। भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने के लिए लंदन में पहले रुपी डिनोमिनेटेड बांड की शुरुआत का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2015 में एफडीआई में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जोकि महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए अति आवश्यक है। इससे उन कूटनीतिक अभियानों की सफलता प्रदर्शित होती है जिनकी शुरुआत यह सोचकर की गई थी कि इनसे विश्व स्तर पर भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

मेक इन इंडिया

भारत के विदेशी अभियानों पर प्रभावशाली प्रतिक्रिया मिली है। रूस ने भारत में केए 226 हेलीकॉप्टरों के संयुक्त निर्माण पर सहमति जताई है। इसके अतिरिक्त *मेक इन इंडिया* अभियान के तहत भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के स्थानीयकरण पर सहयोग देने पर भी रजामंदी जताई है। रूस के रोसएटम और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने स्थानीयकरण के लिए कार्रवाई कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। एल एंड टी और फ्रेंच अरेवा ने जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना का स्वदेशीकरण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा पर सहमति जताई है। एयरबस और टाटा भारत में सी 295 हेलीकॉप्टरों के संयुक्त निर्माण का कार्य करेंगे। एयरबस ने भी हेलीकॉप्टर निर्माण हेतु महिंद्रा के साथ एक प्रारंभिक समझौता किया है। बोइंग एचएच 64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एयरो संरचनाओं का निर्माण करेगा। 12 बिलियन डॉलर मूल्य की जापान-भारत मेक इन इंडिया विशेष वित्त सुविधा की शुरुआत की गई है। वहीं, मारुति जापान में निर्यात के लिए कारों का निर्माण करेगी।

विदेशी निवेश

वर्ष 2015 में एफडीआई में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जोकि महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए अति आवश्यक है। इससे उन कूटनीतिक अभियानों की सफलता प्रदर्शित होती है जिनकी शुरुआत यह सोचकर की गई थी कि इनसे विश्व स्तर पर भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का कुल मूल्य 22 बिलियन डॉलर मूल्यांकित किया गया है। भारत और ब्रिटेन की निजी कंपनियों के बीच 9.2 बिलियन ब्रिटिश पाउंड के सौदे किए गए हैं जिसमें वोडाफोन का 1.3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड का सौदा भी शामिल है। जापान ने अगले पांच वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए 35 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है। दक्षिण कोरिया ने 10 बिलियन डॉलर का वादा किया है (1 बिलियन डॉलर आर्थिक विकास सहयोग निधि के रूप में और 9 बिलियन डॉलर प्राथमिक क्षेत्रों जैसे रेलवे, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन हेतु निर्यात ऋण के रूप में) जर्मनी की ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की दिग्गज कंपनी बॉश ने भारत में तीन नए विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की है और 100 बिलियन ब्रिटिश पाउंड के निवेश की बात की है।

स्मार्ट सिटी

भारत में स्मार्ट शहरों के विकास में सहायता करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदार सामने आए हैं: अमेरिका ने विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, इलाहाबाद को विकसित करने के लिए सहमति जताई है। फ्रांस ने चंडीगढ़, नागपुर, पुदुचेरी पर विशेष जोर देते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना में 2 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश करने को तैयार है।

डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया

माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां डिजिटल इंडिया के कार्यांवयन की दिशा में योगदान देने पर सहमत हैं। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, सिंगापुर और मलेशिया आदि देशों ने कौशल भारत कार्यक्रम के कार्यांवयन में भारत की सहायता करने पर रजामंदी दिखाई है।

स्वच्छ गंगा

जापान और जर्मनी ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए वित्तीय सहायता, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की पेशकश की है।

ऊर्जा सुरक्षा

इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा हेतु भागीदारी पर कूटनीतिक पहल की जा रही है। पिछले वर्ष दिसंबर में पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता के मौके पर भारत की पहल पर 100 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी। यह इस दिशा में यह कदम मील का पत्थर था। इसके लिए भारत ने सचिवालय के लिए जमीन आवंटित की है (गुड़गांव, एनसीआर दिल्ली में) और सचिवालय के निर्माण हेतु 30 मिलियन डॉलर का योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत में परमाणु संयंत्रों की स्थापना और हमारे ऊर्जा मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश से प्राकृतिक यूरेनियम की खरीद हेतु असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता किया जा रहा है।

भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। भूमि सीमा समझौते के अनुसमर्थन से न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा पर सहमति बनी, बल्कि इससे सीमा प्रबंधन सहज हुआ विशेष रूप से अवैध प्रवास, मानव तस्करी, स्मगलिंग आदि की जांच करना आसान हुआ। अब 161 एन्क्लेव में रहने वाले पचास हजार राज्यविहीन व्यक्तियों की वैध राष्ट्रीय पहचान है।

विश्वास बहाली के लिए कूटनीति

पी 5 के अतिरिक्त विश्व के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र- दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, खाड़ी, अफ्रीका, एशिया प्रशांत - भारत की

विश्वव्यापी कूटनीतिक पहुंच के गंतव्य हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के विचार-विमर्श में भाग लेने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूहों जैसे आसियान, ईएएस, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जी-20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन में भी सक्रिय है।

दिल्ली घोषणापत्र 2015 पर सहमति बनी जिसमें भारत-अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए 10 बिलियन डॉलर के ऋण, 600 मिलियन डॉलर के अनुदान सहयोग तथा अगले पांच वर्षों के लिए 50000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। इन प्रयासों से अफ्रीका में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी, साथ ही भारत के साथ सद्भावना उत्पन्न होगी और अफ्रीका में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करना संभव होगा।

नए प्रधानमंत्री के आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले भी हम अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते रहे हैं। मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्र और सरकार प्रमुखों की उपस्थिति से यह बात रेखांकित हुई कि भारत की नई राजनीतिक व्यवस्था अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहती है। इस अवसर ने शुरुआती संबंधों को पुष्ट किया और इसके बाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की तर्ज पर यात्राओं और बैठकों का आदान-प्रदान शुरू हुआ। साथ ही पाकिस्तान से दोबारा बातचीत शुरू हुई। कुल मिलाकर भारत द्वारा की गई इस पहल के परिणाम संतोषजनक रहे। भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। भूमि सीमा समझौते के अनुसमर्थन से न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा पर सहमति बनी, बल्कि इससे सीमा प्रबंधन सहज हुआ विशेष रूप से अवैध प्रवास, मानव तस्करी, स्मगलिंग आदि की जांच करना आसान हुआ। अब 161 एन्क्लेव में रहने वाले पचास हजार राज्यविहीन व्यक्तियों की वैध राष्ट्रीय पहचान है। नेपाल के साथ हमारा विश्वास बढ़ा है। श्रीलंका और मालदीव के साथ भी भारत के संबंध फिर से कायम हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी को नया जीवन मिला है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत द्वारा लचीलापन दिखाने के बावजूद भारत-पाकिस्तान संबंधों में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। फिर भी रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। उम्मीद की एक गली नजर आ रही है जिससे भविष्य में आगे बढ़ने की आशा की जा सकती है।

पी 5

अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं ने *पी 5* देशों के साथ संबंधों में नवशक्ति का संचार किया और इन देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग को गति प्रदान की। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। यह धारणा बन रही थी कि मई 2014 में नई सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत धीरे-धीरे पश्चिम के करीब आने के प्रयास में अपने पुराने मित्र रूस से दूर हो रहा है। इस यात्रा से न सिर्फ रूस से संबंधित चिंता का निवारण हुआ, बल्कि आपसी विश्वास और भरोसा भी बहाल हुआ। साथ ही, एक ध्रुवीय विश्व में मौजूद रहते हुए एक दूसरे की मजबूरियों को समझने का प्रयास किया गया।

एक्ट ईस्ट नीति

नब्बे के दशक में प्रतिपादित लुक ईस्ट नीति ने एक्ट ईस्ट नीति का रूप अख्तियार किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंधों, विशेष रूप से आर्थिक संबंधों पर ठोस पहल करने पर जोर दे रहा है। इसके अतिरिक्त भारत ने *आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि* के लिए 5 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है, जोकि इससे पहले 1 मिलियन डॉलर थी।

द्वीप देश

समुद्री सुरक्षा और नील/महासागर अर्थव्यवस्था के लिहाज से मालदीव, श्रीलंका, मॉरीशस, सेशल्स जैसे देशों में कूटनीतिक पहल करना महत्वपूर्ण है। यह चीन के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक उपाय भी कहा जा सकता है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की मौजूदगी के कारण खाड़ी और पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आईएसआईएस जैसी कट्टरपंथी और हिंसक ताकतों के उभरने के कारण हमारी सुरक्षा को भी खतरा है। अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात और इस वर्ष अप्रैल में सऊदी अरब में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इन विषयों पर चर्चा की गई। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली और एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई। सऊदी अरब की यात्रा से रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिली। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला करने और सुरक्षा के लिए सहयोग पर जोर दिया गया जिसमें खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा शामिल हैं, विशेष रूप से आतंकवादियों द्वारा साइबर स्पेस के दुरुपयोग को रोकना। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को धन मुहैया कराने से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी है।

अफ्रीकी देश

भारत-अफ्रीका फोरम (अक्टूबर, 2015) के दौरान पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप के 41 देशों के राष्ट्र और सरकार प्रमुख दिल्ली पहुंचे। इस फोरम ने अतीत को प्रतिबिंबित करने, सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने तथा एक गतिशील एवं परिवर्तनशील कार्यसूची को सबके सम्मुख रखने का एक सुअवसर

विश्वव्यापी परमाणु निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), ऑस्ट्रेलिया समूह और वेसनर एग्रीमेंट में भारत की सदस्यता को पहले से अधिक समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए भी समर्थन बढ़ा है।

प्रदान किया जिससे आने वाले वर्षों में भारत और अफ्रीका के करीब आने की उम्मीद की जा सकती है। इस दौरान दिल्ली घोषणापत्र 2015 पर सहमति बनी जिसमें भारत-अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए 10

बिलियन डॉलर के ऋण, 600 मिलियन डॉलर के अनुदान सहयोग तथा अगले पांच वर्षों के लिए 50000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। इन प्रयासों से अफ्रीका में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी, साथ ही भारत के साथ सद्भावना उत्पन्न होगी और अफ्रीका में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करना संभव होगा।

बहुपक्षीय मंच

संयुक्त राष्ट्र, जी -20, आसियान, ईएएस, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन सहित प्रमुख बहुपक्षीय मंचों में भारत की बढ़ती सक्रियता ने देश का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, विश्वव्यापी प्रशासनिक ढांचे में सुधार, जलवायु परिवर्तन, समुद्री डकैती, साइबर सुरक्षा, विश्वव्यापी व्यापार वार्ता जैसे मुद्दों पर भारत के अभियानों से अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण बदला है और विश्वव्यापी कार्यसूची का रूपांतरण हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत पर्यवेक्षक की बजाए पूर्ण सदस्य बन गया है। यह स्पष्ट है कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जोकि ओपेक में भारत की सदस्यता को मिले समर्थन में सकारात्मक रूप से नजर आता है। विश्वव्यापी परमाणु निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), ऑस्ट्रेलिया समूह और वेसनर एग्रीमेंट में भारत की सदस्यता को पहले से समर्थन बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए भी समर्थन बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन को जल्द मंजूरी देने को भी रजामंदी मिल रही है, जिसे भारत ने प्रस्तावित किया था।

सीओपी 21 के अंतिम दस्तावेज में भारत के योगदान की विश्व स्तर पर सराहना की जा रही है। इस दस्तावेज में जलवायु के साथ न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। भारत ने इसमें जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सामान्य किंतु भिन्न जिम्मेदारी जैसे सिद्धांत रखे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष जुलाई में रूस के उफा शहर में 7 वीं ब्रिक्स शिखर वार्ता में दस कदम या 10 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तावित किया था, जिसमें व्यापार मेलों, खेल, फिल्म महोत्सवों, कृषि, ऑडिट जैसे क्षेत्रों में अंतर क्षेत्रीय सहयोग की बात की गई थी। 7 वीं ब्रिक्स शिखर वार्ता में भारत समर्थित प्रस्तावों, जैसे 100 बिलियन डॉलर मूल्य के नए विकास बैंक और 100 बिलियन डॉलर मूल्य के मुद्रा रिजर्व पूल को औपचारिक रूप दिया गया।

कनेक्टिविटी

उपक्षेत्रीय और क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कूटनीतिक पहल की गई जिसमें चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के प्रयोग के लिए बांग्लादेश के साथ संधि, कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवा की शुरुआत, भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच मोटर वाहन संधि शामिल है। भारत ने ऐसी परियोजनाओं के लिए 1 अरब डॉलर मूल्य के ऋण के लिए प्रतिबद्धता जताई है जिनसे भारत और आसियान देशों के बीच भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले। भारत द्वारा

(जारी ... पृष्ठ 32 पर)

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-29/2016

(पृष्ठ 24 से जारी ...)

ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण के लिए अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दो प्रमुख गलियारों की प्रगति को गति दी जा रही है जिनमें भारत, ईरान और मध्य एशिया को जहाज, रेल-सड़क मार्ग के जरिए जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे और भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग शामिल हैं जिनसे भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों को काफी लाभ मिलेगा।

संक्षेप में गत 22 महीनों के दौरान सक्रिय और व्यावहारिक कूटनीति ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया है, इससे विश्वव्यापी क्षितिज पर भारत की मौजूदगी बढ़ी है और एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा और कद ऊंचा हुआ है। इससे अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत के लिए सकारात्मक योगदान देना और विभिन्न चर्चाओं को आकार देना संभव हुआ है। ❑